Shri G. Viswanathan: In view of the fact that both the Central and the State Governments are interested in procurement and rationing, may I know from the hon. Minister what is going to be the role of the Central Government in procurement and rationing in future?

Shri Annasahib Shinde: Our policy is well known. We very much desire that the State Governments exert themselves to intensify procurement, and foodgrains is made available to the State Governments.

Copyright Conference at Stockholm

S.N.Q. 11 **Shri Prakash Vir Shastri:**
Shri Ram Avtar Sharma:
Dr. Surya Prakash Puri:
Shri Y. S. Kushwah.
Shri Mahant Digvijai Nath:
Shri Hukam Chand Kachwai:
Shri Shiv Kumar Shastri:
Shri Raghuvir Singh Shastri:

Will the Minister of **Education** be pleased to state

(a) whether it is a fact that an Indian Delegation would be going to attend the Copyright Conference to be held at Stockholm (Sweden);

(b) whether India is put to certain disadvantage for being a member of the Copyright Convention;

(c) whether Government have received any suggestion requesting them to relinquish the membership of the said Convention; and

(d) if so, Government's reaction thereto?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen): (a) to (c). Yes, Sir

(d) The question will be examined after the result of the Stockholm Conference is known.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री: मैं प्रश्न पूछते हुए आप के द्वारा शिक्षा मंत्रालय से विरोध भी प्रकट करना चाहता हूं कि यह प्रश्न जिस समय दिया गया था उस समय तक यह भारतीय प्रतिनिधि मंडल स्वीडेन नहीं गया था । अच्छा यह होता कि उसी समय इस प्रश्न का उत्तर दिया जाता जिस से भारतीय संसद् की प्रतिक्रिया का पता भी इस शिष्ट मंडल को लग जाता, और संसद् की प्रतिक्रिया क्या है इस आधार पर वह अपना निर्णय कर लेता । खैर, जो कुछ हुआ वह हुआ । मैं यह जानना चाहता हूं कि जो प्रतिनिधि मंडल वहां गया है क्या उस को भारत सरकार ने अपने किसी प्रकार के निर्देश दिये हैं कि वहां जा कर वह किस प्रकार का रुख अख्तियार करे ? यदि हां, तो वे क्या हैं ?

Dr. Triguna Sen: Sir, perhaps hon. Members know that the East Asian Seminar on Copyright which was held in New Delhi from January 23 to 30, 1967, adopted a copyright protocol regarding developing countries; this protocol will be considered by the Stockholm conference. The main idea behind the protocol is to enable a developing country to have the right to restrict the protection of works required primarily for educational, scientific and scholastic purposes. It will also enable the developing countries to have the right to issue compulsory licences for translation for the purposes other than education, scientific and scholastic, when such translation in a particular language has not been published by the owner of the rights or is absent in the country concerned within a time to be specified by the domestic law of the country, but these rights will not be exercised without suitable compensation. It will be the intention of the Indian delegation who have gone to Stockholm for participating in this conference that this compensation should be in local currency. The Indian delegation has also been authorised to move for the international protection works of folklore in which India is rich. The

delegation has been authorised also to clearly indicate that if the proposals which are of interest to developing countries were not agreed to, India would have to reserve its position with regard to continuing its membership.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री: जब शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में भारत सरकार ने लगभग यह निश्चय सा कर लिया है कि आगामी पांच वर्षों में विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषायें होंगी तब हम कापीराइट कंवेंशन में अभी तक बंधे हुए हैं, यूनिवर्सल कंवेंशन में भी और बर्न कंवेंशन में भी। यूनिवर्सल कवेंशन वाले अपनी पुस्तकें भारत में छाप रहे हैं केवल अंग्रेजी में। भारतीय भाषा में हम उन का अनुवाद नहीं कर सकते। बर्न कंवेंशन से सम्बन्धित भी इसी प्रकार की कठिनाइयां हैं। इन दोनों स्थितियों में हम एक और निर्णय लेने जा रहे हैं कि विश्वविद्यालय स्तर तक अगले पांच वर्षों में भारतीय भाषाओं में शिक्षा देंगे, दूसरी ओर हमारे यहां पुस्तकों का अभाव है। बर्मा, नेपाल आदि छोटे छोटे देश कापीराइट कंवेंशन से बाहर आ गये तो भी उन की कोई हानि नहीं हुई। रूस जैसे बड़े देश भी कापीराइट कंवेंशन में सम्मिलित नहीं हैं। ऐसी स्थिति में मैं जानना चाहता हूं कि भारत सरकार को क्या आपत्ति है कापीराइट कंवेंशन से बाहर निकलने में जिस से कि हम को भारतीय भाषाओं के माध्यम की शिक्षा की पाठ्य पुस्तकें अधिक से अधिक मात्रा में उपलब्ध हो सकें ?

Dr. Triguna Sen: There is no objection, as I mentioned; they will insist for the protocol to be accepted; if it is not accepted, we reserve the right to think of coming out of the convention, the Berne Convention and the Universal Convention will meet in December; we will have to take the same attitude towards that also. There is no reason that we should not. We will press for acceptance of our proposal for protocol.

श्री रामावतार शास्त्री: मैं जानना चाहूंगा कि जो प्रतिनिधि मंडल गया है उस के कौन कौन से सदस्य हैं और उन के चुनने की पद्धति क्या है। दूसरे जैसा शास्त्री जी ने कहा, भारत कापीराइट कंवेंशन में रहे या न रहे, इस के ऊपर कभी मंत्रिस्तर पर विचार किया गया है ? यदि किया गया है तो उस का परिणाम क्या हुआ ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद): प्रो० शेर सिंह उस के लीडर हैं। शेष में से कुछ सदस्य इस प्रकार हैं :

1. सेक्रेटरी, ला मिनिस्ट्री
2. ज्वायेंट सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री आफ एक्स्टर्नल अफेअर्स
3. रजिस्ट्रार, कापीराइट्स
4. डिप्टी रजिस्ट्रार, कापीराइट्स।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री: माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि क्या कैबिनेट स्तर पर इस पर कभी विचार हुआ है या नहीं, और यदि हुआ है तो क्या निर्णय हुआ।

Dr. Triguna Sen: Oh, Yes. We have taken a decision in the Cabinet.

डा० सूर्य प्रकाश पुरी: क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि कौन से संसार के ऐसे राष्ट्र हैं जो किसी कापीराइट कंवेंशन के सदस्य नहीं हैं, और क्या यह सत्य है कि यूनिवर्सल कापीराइट कंवेंशन का सदस्य होने के नाते अमरीका अपनी पुस्तकें भारत में सिर्फ अंग्रेजी में छपवाता है, और उस का अधिकार सुरक्षित है कि उन का यहां पर हिन्दी अनुवाद नहीं हो सकता ?

श्री प्रकाशवीर शास्त्री: किसी भी भारतीय भाषा में।

Dr. Triguna Sen: I think the hon. member is correct. It is only for that that our delegation has been empowered to press for the protocol to be accepted. Because we are going to develop our regional languages on a large scale, we want to translate; and it is in our interest that we should insist

on an acceptance of the protocol for our benefit.

डा० सूर्य प्रकाश पुरी : मेरे पहले प्रश्न का उत्तर नहीं मिला । मैं ने यह पूछा था . . .

Shri Bhawat Jha Azad: We want notice of that question.

श्री यशवन्त सिंह कुशवाह : क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि स्टाकहोम में प्रतिनिधि मंडल भेजने का निश्चय करने से पहले शासन को कोई ऐसा सुझाव प्राप्त हुआ था कि इस कंवेंशन मे भारत को भाग नहीं लेना चाहिये ?

Dr. Triguna Sen: No, Sir; there was no suggestion.

श्री विभूति मिश्र : क्या मंत्री महोदय बतलायेंगे कि विज्ञान और टेकनिकल शिक्षा की कितनी पाठ्य पुस्तकें ऐसी हैं जो भारत के कापीराइट कंवेंशन का सदस्य होने के नाते उस को सुगमता से प्राप्त नही हो सकतीं ।

Dr. Triguna Sen: It is correct.

An hon. Member: He can use the simultaneous translation.

Mr. Speaker: That was what I was also feeling. Arrangement is there for automatic translation. The hon. minister can use it. He need not use the other minister for getting it translated.

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : इंग्लैंड से जो पुस्तकें छप कर भारत में आती हैं, उन पर प्रति वर्ष हमारी कितनी विदेशी मुद्रा व्यय होती है, और उन पुस्तकों के भारत मे छपने अथवा भारतीय भाषाओं में छपने पर क्या कोई प्रतिबन्ध है ?

Dr. Triguna Sen: Hon. members know that we are deficient in foreign exchange and we cannot afford to pay foreign exchange. That is what we have also told our delegation. We do not want to denounce the human rights and intellectual property which we have accepted. At best we can pay only in our local currency, not in foreign currency.

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : क्या यह सच नहीं है कि अब तक शिक्षा मंत्रालय ने जिन विदेशी किताबो का अनुवाद करने के लिये कापीराइट प्राप्त करना चाहा है उस में चार-चार और पांच-पाच साल लगे, और उस के बाद भी ऐसी शर्तें रक्खी गईं जिन से शिक्षा मंत्रालय अपने उद्देश्य मे सफल नही हो सका ? साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हू कि बर्न कंवेंशन से और यूनिवर्सल कंवेंशन से बाहर निकलने के अपने संकल्प को सीधे पूरा करने के बदले सरकार द्रविड़ प्राणायाम का सहारा क्यों लेना चाहती है ?

श्री भागवत झा आजाद : यह बात सच है कि जो हमारे दो कंवेंशन्स हैं उसमें रहने से कठिनाईयां हैं । अस्तु उन लोगों को हम ने यह निर्देश दिया है कि अगर प्रोटोकोल के अनुसार अविकसित देशों के लिये बीस वर्षों की जो छूट मांगी गयी है वह न मिले तो, जैसा माननीय मत्री जी ने कहा, हम ने यह अधिकार सुरक्षित रक्खा है कि हम उससे बाहर निकल सकें ।

Shri Bal Raj Madhok: Since we are members of both Berne Convention and Universal Convention and the Stockholm Conference is only concerned with Berne Convention, even if our suggestions are accepted there, we will still be in the other Convention and the USA and other countries may not be bound by what we suggest there. May I know, in view of these circumstances, if the United States of America or any other country still persists that these copyrights must be with them, are we prepared to deal with them in the same way and say that if they do not agree we will get out of it?

Dr. Triguna Sen: I hope the hon Member should not have any doubt in his mind that our attitude will be different. The Universal Convention will meet in December. We will have the same attitude for the benefit of our own country.

Shri Hem Barua: In reply to part (b) of the original question the hon. Minister has said: "Yes". That means we are facing certain disadvantages because of our membership of these Conventions. And, by now, what are the disadvantages, they have come to light, and every one of us has come to know what are those disadvantages. Since the hon. Minister has said "Yes" to part (b) of the Question, may I know whether these disadvantages were not enough material on which the Government could have taken a decision to relinquish the membership of the same convention?

Dr. Triguna Sen: Sir, we have suggested and empowered the delegation to press for the protocol that has been accepted in the Delhi Seminar. We have advised them, because we are meeting with disadvantages—if we want to translate a book and ask for the copyright it takes years and years and, secondly, we have no foreign exchange to pay and, therefore, you can easily understand our difficulties—if they do not agree we will walk out. There is no other way.

Shri Hem Barua: A dynamic Education Minister as we have today should be able to take a decision immediately.

Dr. Triguna Sen: We have taken the decision and advised the delegation to take the decision on the spot.

श्री शिवचन्द्र झा: जो शिष्टमंडल स्टाकहोम जा रहा है क्या उसको ऐसा भी निदेश दिया गया है या यहां पर इस बात पर भी गौर किया जाएगा कि भारतीय लेखकों की जिन रचनाओं का विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है और जो लेखक गुजर चुके हैं, उन रचनाओं का जो रिम्युनरेशन है वह ठीक तरह से रीयलाइजड हो और गुजरे हुए लेखक के साहित्य प्रचार में या उसके स्मारक के रूप में उस रीयलाइजड की गई राशि का इस्तेमाल हो ? उन रचनाओं के जो रिम्युनरेशन है वे ठीक और मुसतेदी से रीयलाइजड हों इस पर भी क्या गौर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा ?

मैं एक मिसाल देता हूं । विद्यापति की रचना का ट्रांस्लेशन श्री आर्चर ने जो कि पटना के कलैक्टर थे 1942 में किया है । "लव सांग्ज आफ विद्यापति" । ऐसे लेखकों को जो गुजर चुके हैं और कापीराइट के अधिकारों के मुताबिक जिन को रिम्युनरेशन अपने नाम से या जो संस्था स्थापित हुई है उस के नाम पर मिलना है, क्या उस रिम्युनरेशन को सरकार मुस्तैदी से रीयलाइज करेगी या नहीं और क्या इस बात पर स्टाकहोम कान्फ्रेंस में विचार होगा या नहीं ?

श्री भागवत झा आजाद : अगर मैं माननीय सदस्य के प्रश्न को ठीक तरह समझा हूं तो इसका जवाब यह है कि इस कान्फ्रेंस में जो हम विदेशी लेखकों को यहां पर प्रीटैकशन दे रहे है उस पर विचार होगा । अगर यह प्रोटोकोल स्वीकृत हो गया तो उसके अन्दर अविकसित देशों को इन नियमों से छुट्टी मिल जाएगी । इस सम्बन्ध में और अन्य सभी प्रश्नों पर हम विचार कर रहे है ।

Shri D. C. Sharma: The Berne Convention and the Universal Convention have worked not with disadvantages—that is a very mild word—but have worked to the detriment of most of the developing countries and some of the developed countries also have turned their back both on the Universal Convention and the Berne Convention. May I know why the Government is wasting its foreign exchange in sending this delegation to Stockholm to discuss a question which needs no discussion under the circumstances of our country and which should have been decided long ago in order that our country should progress in terms of knowledge of science and other things?

Dr. Triguna Sen: The hon. Member knows that so long for various reasons perhaps the Government did not think it wise to take such a step. But now that we have decided to go in a big way to develop the regional languages and we are finding it difficult, we have taken that stand. The hon. Member

has asked why have we sent the delegation. Since we are members and we have not come out of the Convention it is desirable that we should go there stress our point gently and like gentlemen come out. Perhaps other countries will also understand our viewpoint if we do that

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Central Wheat Pool

*456. **Dr. Karni Singh:**
Shrimati Nirlep Kaur:

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state.

(a) whether Government have laid down any specific policy to govern contribution by the States to the Central Wheat Pool,

(b) if so, the salient features thereof, and

(c) the total quantum of wheat proposed to be collected under this pool?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) All the States have been requested to offer maximum quantities of foodgrains possible to the General Pool. No separate policy has been laid down for wheat

(b) Does not arise.

(c) No target has been fixed for collection of indigenous wheat under Central Pool

I.A.C.

*459. **Shrimati Suseela Gopalan:**
Shri A. K. Gopalan:
Shri K. Ramani:
Shri Tridib Kumar Chaudhuri:
Shri S. C. Samanta:

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) whether the expenses of the Indian Airlines Corporation on imports and payment of instalments have gone up after devaluation;

(b) if so, the extent of the rise;

(c) whether Indian Airlines Corporation is likely to incur loss as a result thereof; and

(d) the steps Government propose to take in the matter?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh): (a) to (c). As a result of devaluation the liability of the Corporation has gone up by Rs 1084.42 lakhs. The consequential loss during 1966-67 has been estimated at Rs 200 lakhs.

(d) The proposals submitted by the Corporation for increasing the fares and freights to offset, *inter alia* the effect of devaluation is under examination

Subsidies on Food and Fertilisers

*460 **Shri A. K. Gopalan:**
Shrimati Suseela Gopalan:
Shri Bhogendra Jha:
Shri K. M. Madhukar:
Shri Yashpal Singh:
Shri S. C. Samanta:
Dr. Ranen Sen:
Shri D. S. Patil:
Shri K. Ramani:

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether Government have decided to curtail subsidies on food and fertilisers;

(b) if so, the extent of the curtailment; and

(c) the circumstances which led the Government to take this decision?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) to (c). A statement is placed on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-620/67]